>

Title: Need to cover more villages under 'Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Scheme' in Rajasthan.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, राजस्थान राज्य वर्तमान वसुन्धरा सरकार के प्रयासों से बीमारू राज्यों की श्रेणी से निकल कर विकासशील राज्यों की श्रेणी में परिगणित होने लगा है। विकास का मूल आधार विद्युत ऊर्जा है। यद्यपि राजस्थान में जल विद्युत, ताप विद्युत तथा परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न विद्युत से पर्याप्त विकास कार्य सम्पन्न हो रहे हैं। परन्तु पूर्व में विद्युतीकरण के नाम पर राजस्थान में केवल पंचायत मुख्यालयों को ही विद्युतीकरण कर यह मान लिया गया कि पूरी पंचायत विद्युतीकृत हो गई है, जबकि एक ही पंचायत में कई उससे भी बड़े राज स्वगांव ढ़ाजियां, मजरे होते हैं, वे सब विद्युतीकृत होने से बचे हुए हैं। अतः राजस्थान के अधिकांश गांव/मजरे/ढ़ाणियां अभी भी बिजली से वंचित है। राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 41 प्रस्ताव प्रेषित किये थे जिसमें से 27 योजनाओं को ही स्वीकृति दी गई। 12 प्रस्तावों पर सिद्धांततः स्वीकृति दी गई। हजारो मजरे, ढ़ाणिया, राजस्वगांव अभी विद्युत की पहुंच से बाहर हैं। अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान की सीमावर्ती स्थिति, पिछड़ेपन, विषम भौगोलिक स्थिति को दÂिटगत रखते हुए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत राजस्थान के बचे हुए सभी गांवों, ढ़ाणियों और मजरों को सम्मिलित किया जाये और वहां बिजली पहुंचाई जाये।